

Vol III Issue I Feb 2013

Impact Factor : 0.2105

ISSN No : 2230-7850

Monthly Multidisciplinary
Research Journal

*Indian Streams
Research Journal*

Executive Editor

Ashok Yakkaldevi

Editor-in-chief

H.N.Jagtap

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2230-7850

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences,
University of South Carolina Aiken, Aiken SC
29801

Hasan Baktir
English Language and Literature
Department, Kayseri

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore
University of Management Sciences [PK]

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest,
Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest,
Romania

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

Xiaohua Yang
PhD, USA
Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Titus Pop

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devruk, Ratnagiri, MS India
Ex - VC. Solapur University, Solapur

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University,
Solapur

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur
University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

R. R. Yalikar
Director Management Institute, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education,
Panvel

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science
YCMOU, Nashik

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji
University, Kolhapur

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University,
Mumbai

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance
Education Center, Navi Mumbai

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Alka Darshan Shrivastava
Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College,
Indapur, Pune

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director, Hyderabad AP India.

S.KANNAN
Ph.D., Annamalai University, TN

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust), Meerut

S. Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Satish Kumar Kalhotra

**Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net**

ORIGINAL ARTICLE



“विश्व भारत एवं पर्यावरण विधीएक अध्ययन”

आशीष श्रीवास्तव, आशुतोष बैटानी

एम . वी . खालसा लॉ कॉलेज इन्डौर (म . प .)
श्री वैष्णव लॉ कॉलेज इन्डौर (म . प .)

I-सार (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र में पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण के तत्व पर्यावरण संरक्षण संविधित प्रावधान संविधान एवं विभिन्न भारतीय विधियों तथा विश्व स्तर पर क्या हैं? तथा पर्यावरण संरक्षण से संविधित मान उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का वर्णन किया गया है उपलब्ध विधियों का प्रभाव पूर्णतः न हो पाने के लिए सुझाव दिये गये हैं।

II-प्रच्छावना - (Introduction)

“पर्यावरण” शब्द से अभिप्राय है -परिष्टुआवरण अर्थात् मानव के चारों ओर पाया जाने वाला वातावरण | इस पर्यावरण के अंतर्गत जल वायु अग्नि इत्यादि आते हैं | इन्हीं तत्वों में प्रदूषण होने के कारण मानव जाति को सर्वाधिक कठिनाई का समना करना पड़ रहा है | दूसित पर्यावरण के कारण अनेक लाइलाज संकामक गोंदों की उत्पत्ति हो रही है | मानव की औसत आयु 100 वर्ष से घटकर 60 वर्ष रह गई है | ऐसा कहा जाता है कि मानव जितना प्रकृति से दूर रहेगा उतना ही इसे समस्याओं का समना करना पड़ेगा | भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जाये तो वैदिक संस्कृति में मानव प्रकृति की पूजा व उसके संरक्षण में रहने में ही सुख का अनुभव करता था | अतः उस काल में उपर्युक्त समस्याओं का उद्भव नहीं हुआ था | लेकिन इस समय सभी समस्यायें मानव जाति को समाप्त करने में संलग्न हैं और इन समस्याओं की पर्यावरण विशेषज्ञों ने अपने शोध अध्ययनों में स्पष्ट भी किया है।

III-तक्फ - (Rational)

एम . री . मेहता
वनाम
भारत संघ
(AIR 1985 SC 652)

वंद करने का आदेश जारी किया जाये क्योंकि इन कारखानों से निकलने वाला मलवा गंगा नदी में बहाया जा रहा है जिसके कारण गंगा नदी का जल प्रदूषित हो रहा है | इस बाद में प्रत्यर्थियों ने अपने वचाव में अनेक तर्क दिये थे | मान उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यर्थियों के तर्कों को अस्वीकार करते हुये वर्षशोधन कारखानों को तत्काल वंद करने का आदेश पारित किया था | इसके साथ ही मान उच्चतम न्यायालय ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि बेरोजगारी और राजस्व की हानि की अपेक्षा लोगों के प्राण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण का महत्व अधिक है।

पर्यावरण संबंधी विश्वविद्यालय प्रमुख कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय

संगठनों द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिये कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य यहाँ समस्याओं को गिनाने का नहीं वरन् विश्व एवं भारत में इन समस्याओं से निपटाने के लिये क्या उपाय एवं सुझाव पर्याप्त हैं?

IV-उद्देश्य - (Objectives)

हमारे शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य है अपने आपको पर्यावरण के पति जागरूक बनाना क्योंकि मैं इस पर्यावरण का एक अभिन्न अंग हूँ - अर्थात् पर्यावरण के प्रति धर्कों में मानव का एक निश्चित स्थान है जिस प्रकार आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भयावह रूप धारण करती जा रही है और यदि यह समस्या धूं ही बढ़ती रही तो संपूर्ण पर्यावरण ही नष्ट हो जायेगा तो नह म होंगे न आप | क्योंकि पर्यावरण का अर्थ है - परिष्टुआवरणडचारों और का वातावरण जिसमें सब कुछ शामिल है . जो दिखाई देता है वह भी और जो नहीं दिखाई देता वह भी।

इसके अंतर्गत पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण उसके कारण सामाजिक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण के निवारण को ठोस उपाय और उन्हें कारगर करने के तरीके उनके उपयुक्त होने के बावजूद ठीक तरह से प्रवर्तित होना भारत में विधिक एवं सांविधानिक प्रावधानों की उपयोगिता कहां तक कारगर रही है और कहां तक नहीं आदि का मूल्क अध्ययन कर हर हालत में समाज को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने का संकल्प है | सर्वप्रथम हमने कहा कि हम जागरूक होना चाहते हैं क्योंकि हम यह

Title : “विश्व भारत एवं पर्यावरण विधीएक अध्ययन”

Source: Indian Streams Research Journal [2230-7850] | आशीष श्रीवास्तव, आशुतोष बैटानी yr:2013 vol:3 iss:1

जानते हैं कि जब हम जागरूक होयेंगे तभी परिवार जागरूक होगा और जब परिवार जागरूक होगा तभी समाज जागरूक होगा और जब समाज पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा तो एक गांव जागरूक होगा और इसी क्रम में एक गाड़ और फिर संपूर्ण विश्व की बारी आती है।

अतः इस शोध के माध्यम से हम स्वयं तथा संपूर्ण मानव जाति को संचेत कर देना चाहते हैं कि पर्यावरण उस शक्ति की तरह है जिसका सदुपयोग कर हम चाहें तो शांति एवं सृष्टि के साथ जीवित रह सकते हैं और दुरुपयोग कर अपने विनाश को आमंत्रित कर सकते हैं।

V - परिकल्पना - (Hypothesis)

वर्तमान में पर्यावरण के प्रदूषण के प्रमुख कारण जल वायु भूमि तथा अम्लीय वर्षा द्वारा पर्यावरण अति जनसंख्या से पर्यावरण का असंतुलित होना जंगलों की समाप्ति और जंगलों तथा पालतए पशुओं का विनाश विभिन्न जैसों की समाप्ति भूमि मृदा क्षण से रेगिस्ट्रेशन का उद्भाव तथा उसमें वृद्धि प्रकृतिक साधनों जैसे जल प्राकृतिक ईंधन आदि की समाप्ति भूमि के अंतर्जल की समाप्ति के कारण भूमि स्थलन् विश्व तापमान में वृद्धि का ग्रीन हाउस पर विपरीत प्रभाव एवं ऑजोन परत का क्षय तथा प्रकृति की धमकी है। भारत में पर्यावरण प्रदूषण के लिये विभिन्न उपचार उपलब्ध हैं जिनमें से कोमन लॉ उपचार कानूनी उपचार और सांविधानिक विधि उपचार प्रमुख हैं।

VI - अनुसंधान विधि - (Research Methodology)

उक्त समस्या के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रदूषण के निवारण के ठोस उपायों के लिए हुई वायुकारी अनुशंसाओं भारत के माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन भारतीय संसद अथवा विधानसभा औं द्वारा पारित कानून एवं ऑल इंडिया रिपोर्ट (A.I.R.) किमिल लॉ जर्नल्स प्रतिवेदित किरण (Year Book) प्रतिवेदित वर्षिकी मध्यप्रदेश एवं भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों से सामग्री का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गये हैं।

VII - अनुसंधान क्षेत्र एवं संपूर्ण एकत्रीकरण - (Universe Sample Collection)

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में अनुसंधान का क्षेत्र संपूर्ण भारत एवं विश्व है।

VIII - शोध तकनीक - (Research Tool and Techniques)

सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण समस्या का विश्लेषण कर परिकल्पना निर्मित की गयी उस परिकल्पना का अन्वेषण तकनीक के आधार पर समस्या से संबंधित मामलों पर माननीय न्यायालयों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उपलब्ध कानून दंड प्रक्रिया सहिता भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं एवं संघोंधित धारा औं कोमन लॉ उपचार सांविधानिक उपचार विधिक प्रावधान समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों एवं डंटा औं माननीय न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण एवं पीडितों से वर्चां उपरांत निष्कर्ष निकाले गये हैं एवं उनको परिकल्पना औं की कौशिकी कहा गया है जिससे अनुसंधान परिष्कृत रूप में सामने आया है।

IX - अवलोकन या विश्लेषण - (Observation or Analysis)

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भूमण्डलीय तापन (Global Warming) तथा उससे होने वाले भावी जलवायु परिवर्तनों भूमण्डलीय पर्यावरणीय एवं पर्यावरणीय स्थितिकीय समस्या औं तथा उनके प्रभावों के प्रति जागरूक हैं तथा भूमण्डलीय तापन के नियंत्रण तथा मानवजनित जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये कई प्रयास प्रारंभ कर दिये गये हैं। कई संगठन कार्यक्रम तथा परियोजनायें हैं औंजोन परत की अल्पता तथा हारितगृह प्रभाव (Green House Effects) में वृद्धि से निपटने के लिये विश्व स्तर पर प्रयास हो रहे हैं।

ओंजोन परत नष्ट करने वाले CFCs (Slorofluro Corban) के उत्पादन पर रोक लगाने के लिये “मार्टिफ्लो प्रोटोकॉल” लंदन में 5 से 7 मार्च 1989 में विश्व के 180 देशों के अधिकारियों वैज्ञानिकों उद्योगपतियों आदि की “ओंजोन परत की अल्पता” पर आयोजित संगोष्ठी कलिप्य ऐसे उदाहरण हैं जो पर्यावरणीय समस्या औं के निदान के लिये अंतर्राष्ट्रीय सक्रिय सहयोग को इंगित करते हैं। पांतु दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि गरजनैतिक दैवर्धित्व विश्व समुदाय को सर्व नाश के कागर पर खड़ा करने के लिये आमादा है।

सन 1991 के जनवरीफरवरी माह में घटित इराक एवं वहुगणीय सेनाओं के बीच घमसान खाड़ी युद्ध ने खाड़ी देशों के पर्यावरण को जिस तरह से प्रदूषित किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मृद्यु की वर्षरता अपी समाज नहीं हुई है तथा उसे स्वयं पर्यावरण के स्थान पर अधिक एवं राजनीतिक लाभ अधिक प्राप्त है। भूमण्डलीय पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण परिस्थिति कोरा संतुलन परिस्थिति तंग की स्थिता एवं जैव विविधता (Biodiversity) को कायम रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कई समेलनों द्वारा कई समेलनों संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया गया है तथा कई महत्वपूर्ण संघियों एवं धोषणाओं पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

प्रथम पृथ्वी समेलन (रियो सम्मेलन) :

पृथ्वी तथा उसके पर्यावरण की सुरक्षा एवं परिस्थितिक योग्यता को बनाये रखने के लिये जैव विविधता को समृद्ध करने के लिये डिजिनेरी नार में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (United Nations Conference on Environment and Development-UNCED) मन 1992 में 3 से 14 जून तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के प्रमुख पाँच मुद्दे निम्नानुसार नियंत्रित किये गये थे -

- 1) भूमण्डलीय तापमान में वृद्धि (Global Warming),
- 2) वन संरक्षण

- 3) जैव विविधता (Biodiversity)
- 4) एजेण्डा (कार्यक्रम) 21 तथा
- 5) रियो सम्मेलन घोषणा पत्र.

इसके बाद द्वितीय पृष्ठी सम्मेलन 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल का वर्णन किया गया है।

भारतीय न्यायालयों द्वारा गये निर्णय -

1. एम . सी . मेहता बनाम भारत संघ (AIR 1985 SC 652)

बंद करने का आदेश जारी किया जाये क्योंकि इन कारखानों से निकलने वाला मलवा गंगा नदी में बहाया जा रहा है जिसके कारण गंगा नदी का जल प्रौद्योगिक हो रहा है। इस बाद में पत्तरियों ने अपने वचाव में अनेक तर्क दिये थे। मान उच्चतम न्यायालय ने पत्तरियों के तर्कों को अस्वीकार करते हुये चर्चाओं को तकाल बंद करने का ओडिशा पारित किया था। इसके साथ ही मान उच्चतम न्यायालय ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि बेरोजगारी और राजस्व की हानि की अपेक्षा लोगों के प्राण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण का महत्व अधिक है। पर्यावरण संबंधी विश्वस्तरीय प्रमुख कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिये कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया गया है।

2. पीपुल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (1997) 3 SCC 433

इस मामले में मान उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अधिकारित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रमंगिदा के प्रावधान जो हमारे संविधान द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों की विशिष्टीकरण करते हैं और प्रभावी करते हैं उन पर न्यायालयों द्वारा उन मूल अधिकारों के पहले के रूप में अवश्य निर्भर किया जा सकता है और वे इस प्रकार प्रवर्तनीय हैं।

3. वैल्लोर सिलिंग्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996) 5 SCC 647, 659-660

इस मामले में मान उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अधिनिधरित किया गया है कि यह विधि की लगभग स्वीकृत प्रतिपादना है कि रूढ़िजन्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम जो विधि के विरुद्ध नहीं हैं उनको धरेलू विधियों सम्मिलित समझा जायेगा और न्यायालयों द्वारा उनका अनुसरण किया जायेगा।

4. गूणीकृतनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) 1 SCC 645, 730.

“राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।” किसी अधिकार को मूल अधिकार मानने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसका अभियक्त रूप से संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया हो जो कि मूल अधिकार से संरक्षकरण करता है। संविधान के भाग 3 और भाग 4 में के उपवंश जो क्रमशः मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंध रखते हैं एक दूसरे के पूरक और अनुप्रकृत हैं। मूल अधिकार भाग 4 में निर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ नाम दें और इसलिये उनको अर्थान्ययन निदेशक तत्वोंके वृष्टिकोण से किया जाना आवश्यक है। उक्त समस्त मामलों में माननीय न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण एवं उपचार के संदर्भ में निर्णय दिये हैं।

पर्यावरण के लिये सांविधानिक व्यवस्था :

भारत का संविधान संभवतः विश्व के अनोखे संविधानों में से एक है जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिये विशेष उपवंश किये गये हैं। प्रारंभ में मूलतः संविधान में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिये कोई विशेष उपवंश नहीं थे परंतु 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान के भाग 4 में गञ्च के नीति निदेशक तत्वों द्वारा 48 कह में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के प्रावधानों के साथ अभियक्त रूप से “मूल कर्तव्यों” में भी पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिये विशेष उपवंश किये गये जो अनुच्छेद 51 द्वारा हृष्ट हैं। संविधान का 42 वां संशोधन अधिनियम स्टाकहोम घोषणा की प्रतिक्रिया में जिसके माननीय पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा 1972 में स्वीकार किया गया था अंगीकृत किया गया है।

पर्यावरण संबंधी विधायी शक्तियां :

साधारण तथा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान कानूनों (Statutes) द्वारा किया जाता है। अतएव पर्यावरण की दृष्टि से विधायी शक्तियां के आवंटन की जानकारी महत्वपूर्ण है। भारत ने परिसंचालक शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें विधायी शक्तियों को संघ तथा राज्यों के मध्य विभाजित किया गया है।

सांविधानिक योजना के अधीन विधायी शक्तियांको विभाजित करने हेतु संविधानमें तीन सूचियां निर्मित की गई हैं:- संघ सूची राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संविधान के अधीन अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति भारत की वाध्यता हेतु प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 253 में विशेष रूप से संसद को शक्ति प्रदत्त की गई है कि “संविधान के अन्य उपवंशों में किसी वात के होते हुये भी संसद को किसी अन्य निकाय में किये गये किसी विनियोग के कार्यान्वयन के लिये भारत के संपूर्ण गाज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये कार्पाई विधि वानाने की शक्ति है। वस्तुतः यह है कि भारत में पर्यावरणीय विधिशास्त्र का विकास रिट अधिकारिता द्वारा हुआ है।

न्यायिक सक्रियतावाद और लोकहितवाद या सामाजिक कार्यवाहीवाद की युक्ति का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में प्रतिपादन से प्रक्रियालयक अधिकारिता में वडा भारी परिवर्तन हुआ है और इसने मानव अधिकार की भावना से युक्त पर्यावरणीय विधिशास्त्र के विकास में बड़ी प्रेरणादायक भूमिका अदा की है।

X - परिणाम खोज - (Findins)

जैसा कि सर्वीविदित है कि आज मानव जाति 21 वीं शदी में प्रवेश कर चुकी है लेकिन साथ ही इन विभिन्न क्षेत्रों जैसे ल सामाजिक भौतिक जैविक गणनैतिक आदि में अनेक पर्यावरण समस्याओं का समान करना पड़ रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीव वैज्ञानिक रसायनज्ञ अर्थशास्त्री समाजशास्त्री मानवशास्त्री मनोवैज्ञानिक भूगोलवेत्ता विकित्सक अधिवक्ता तथा अभियंता सभी इस विषय पर वित्तित हैं और इन समस्याओं का हल हूँडने में प्रयासमर्त हैं।

X - सुझाव - (Suggestions)

आधुनिक पर्यावरण समस्या के निवारण के प्रावधान :

आधुनिक पर्यावरण समस्या का वैदिक समाधान एवं पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध उपाय का वर्णन किया गया है। जिसको यहां संक्षेप में दिया जा रहा है। इन समस्याओं के निराकरण हेतु मानव को पुरावेदों की ओर लौटना होगा जिसमें कि प्रकृति व मानव के संतुलन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है तथा उनमें प्रतिपादित नियमों व प्रावधानों का कठोरता से पालन करना होगा तभी मानव जीवन पुः सुखमय वन संरक्षण तथा इस वैदिक प्रार्थना रूपी आर्थिक विकास को ग्रहण कर सकेगा कि -

“तच्छुद्विवहितं पुरस्वाच्युक्तुमुच्चरत् पञ्चेम शरदः शतम् शरदः शतम्।
शुण्याम शरदः शतम् प्रवावाम शरदः शर्तुं भूपश्चः शरदः शतात्॥

वैदिक उपायों को हम इस कम से विवेचित कर सकते हैं प्रकृति आकाश वायु जल यज्ञ जिसका वर्णन वेदों में किया गया है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध उपाय मानव जाति हमेशा से करती आई है। इसके परिणामस्वरूप अनेक पकार के उपायों का प्रादुर्भाव होता जा रहा है और उनका उपयोग भी किया जाता रहा है 5 इन्हीं उपायों का संक्षिप्त वर्णन यहां किया जा रहा है :-

1) आध्यात्मिक उपाय 2) विद्यार्थी उपाय

भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास एक शतक से अधिक पुराना है जिसके माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के उपायों को विद्वार से रेखांकित किया गया है। जिसमें से भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अतिरिक्त अन्य अधिनियमों में भी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित उपवंश पाये जाते हैं।

ये अधिनियम हैं :- समुद्र तट उपताप (मुम्बई तथा कोलावा) अधिनियम 1953 भारतीय मुद्राधिकार अधिनियम 1882 एवं उत्तरी भारत नहर और जल विकास माल अधिनियम 1873।

स्वतंत्र भारत में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिये निम्न विषयों पर अधिनियम पारित किये गये :- जल प्रदूषण से संबंधित अधिनियम वायु प्रदूषण संबंधी अधिनियम विकिरण (Radiation) से संबंधित अधिनियम कीटनाशी संबंधित अधिनियम साधारण पर्यावरण से संबंधित अधिनियम खाद्य अपमिश्रण संबंधी अधिनियम।

इनके अलावा कई अन्य नागरिक एवं सामाजिक समितियों द्वारा पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये महत्वपूर्ण अनुशंसायें की गई हैं :- न्यायिक सक्रियतावाद सर्विधानिक उपाय योजनागत उपाय दण्ड व्यवस्था के तहत भारतीय दण्ड संहिता 1860 सामाजिक प्रतिक्रिया विश्व द्वारा उपाय जिनका विवरण ऊपर विस्तार से किया गया है।

वर्तमान में पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ये अधिनियम प्रभावी रूप से प्रचलित हैं : वन अधिनियम 1927 वन प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 वन संरक्षण अधिनियम 1980 वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 सार्वजनिक दायित्व वीमा अधिनियम 1991 गांधीय पर्यावरण अधिकारण अधिनियम 1997 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1994 एवं गांधीय पर्यावरण अपील प्राधिकारी अधिनियम 1997।

XII - उपसंहार - (Conclusion)

विश्व स्तर पर अति महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी प्रमुख कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पृथ्वी सम्मेलन भारतीय संविधान एवं विभिन्न भारतीय विधियों में पर्यावरण संरक्षण प्रवाधन उपलब्ध होने के बावजूद हमारा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है प्रस्तुत शोध पत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए मुझावों पर अमल अत्यंत आवश्यक है। यह विषय न सिर्फ शाय्य का विलक्षण अति गंभीर है क्योंकि इस पर ही मानव जाति का भविष्य निर्भर है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| 1 . पर्यावरण भूगोल | - | सविन्द्र सिंह |
| 2 . पर्यावरण (प्रवाधन एवं विकास) | - | राजकुमार गुर्जर |
| 3 . पर्यावरण | - | डॉ . महिमा विपाठी |
| 4 . फारेस्ट इन इण्डिया | - | वी . पी . अग्रवाल |
| 5 . सैनिटरी इनवायरमेंट | - | मुमीर के . भटनागर |
| 6 . पर्यावरण दर्जन (1994) | - | पी . ओम प्रसाद |
| 7 . पर्यावरण विधि | - | डॉ . जयजय राम उपाध्याय |
| 8 . भारत का सावधान | - | जय नारायण पाण्डेय |
| 9 . भारतीय दण्ड संहिता 1860 | - | अमरगंगेन्द्र यादव |
| डॉ . मुरलीधर चतुर्वेदी | | |
| ओ . पी . श्रीवास्तव | | |

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| 10 . सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 | - | कानून प्रकाशक (अधि.), |
| 11 . दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 | - | रत्नलाल थीरजलाल |
| 12 . अपकृत्य विधि | - | डॉ . एस . के . कपूर . |

अन्य अधिनियम :

- 1 . वन अधिनियम 1927 .
- 2 . बन्य पाणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 .
- 3 . जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 .
- 4 . वन संरक्षण अधिनियम 1980 .
- 5 . वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 .
- 6 . पर्यावरण ह्यासंरक्षण ह अधिनियम 1986 .
- 7 . सार्वजनिक वायित्व वीमा अधिनियम 1991 .
- 8 . गांधीजी पर्यावरण अधिकारण अधिनियम 1997 .
- 9 . खाद्य अपमिथ्रण निवारण अधिनियम 1994 एवं
- 10 . गांधीजी पर्यावरण अपील प्राधिकारी अधिनियम 1997 .

अन्य सामग्री :

- 1 . ऑल इण्डिया रिपोर्टर (A.I.R.)
- 2 . क्रिमिनल लॉ जर्नल्स
- 3 . प्रतिवेदिता किरण (Year Book) 2005 ते 2011 .
- 4 . प्रतिवेदिता दर्पण वार्षिकी - 2005 .

Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper. Summary of Research Project, Theses, Books and Books Review of publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- * International Scientific Journal Consortium Scientific
- * OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net